



भारतीय सन्दर्भ में उच्च शिक्षा का विकासात्मक अध्ययन DR. DEVENDR SINH CHAMYAAL, DR. DEVENDR SINH BISHT

डॉ. देवेन्द्र सिंह चम्याल¹ | डॉ. देवेन्द्र सिंह बिष्ट²

^{1,2} शिक्षा संकाय, सोबन सिंह जीना वि०वि०, परिसर अल्मोड़ा (उत्तराखण्ड).

ABSTRACT:

भारत में स्वतन्त्रता प्राप्ति के समय में उच्च शिक्षा का संख्यात्मक विकास अत्यन्त त्वरित गति से हुआ है, एवं उसका विकास आदि से अन्त तक अनियोजित रहा है। स्वर्गीय जवाहरलाल नेहरू के अनुसार— “यदि विश्वविद्यालय अपने कर्तव्यों का समुचित रूप से पालन करें, तो राष्ट्र एवं जनता का कल्याण हो सकता है।” क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग एशिया— 2022, में IIT- बाम्बे ने 42वां स्थान हासिल किया उसके बाद IIT- दिल्ली ने और IIT- मद्रास 54वें स्थान पर हैं। वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग— 2022 में शीर्ष 400 सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालयों में बेंगलुरु स्थित भारतीय विज्ञान संस्थान (IISc) सहित तीन भारतीय विश्वविद्यालय ने अपनी जगह बनाई है। आई०आई०एससी० को पिछले वर्ष की तरह 301–350 ग्रुप में रखा गया। उच्च शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य सत्य की खोज करना है। इसके लिये मौलिक शोध-कार्यों का विकास आवश्यक है।

KEYWORDS:

भारतीय, उच्च, शिक्षा, विकासात्मक, अध्ययन।

प्रस्तावना—

भारत का उच्च शिक्षा तंत्र विश्व में तीसरे स्थान पर आता है। इससे आगे अमेरिका और चीन है। भारत में प्रतिवर्ष करीब 25 लाख स्नातक निकलते हैं, जो भारत के संबंधित युवा वर्ग का महज 10 फीसदी है। भारतीय विश्वविद्यालय जिन्हें विश्वस्तरीय शोध और बौद्धिक गतिविधियों का केंद्र होना चाहिए था, छल-कपट के अड्डे बने हुए हैं। आधुनिक ज्ञान आधारित वैश्विक अर्थव्यवस्था में अपनी पूर्ण क्षमता का दोहन करने के लिए भारत को विश्व के प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों की आवश्यकता है।

क्यूएस एशिया रैंकिंग— 2022 सूची में नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर (एनयूएस) शीर्ष पर काबिज है। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग एशिया 2022 में कई भारतीय उच्च शिक्षा संस्थानों और विश्वविद्यालयों ने भी जगह बनाई है। रैंकिंग में IIT- बाम्बे ने 42वां स्थान हासिल किया उसके बाद IIT- दिल्ली ने और IIT- मद्रास 54वें स्थान पर हैं।

टाइम्स हायर एजुकेशन (THE) वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग, 2022 में शीर्ष 400 सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालयों में बेंगलुरु स्थित भारतीय विज्ञान संस्थान (IISc) सहित तीन भारतीय विश्वविद्यालयों ने अपनी जगह बनाई है। हालांकि, किसी को भी 200 ग्लोबल लीग टेबल में स्थान नहीं मिला। आई०आई०एससी० को पिछले वर्ष की तरह 301–350 ग्रुप में रखा गया। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान रोपड़ ने 351–400 ग्रुप में अपना स्थान बनाए रखा। वहीं मैसूर स्थित निजी वि०वि० जेएसएस एकडमी ऑफ हायर एजुकेशन एंड रिसर्च ने ग्लोबल रैंकिंग में अपनी शुरुआत की और 351–400 ग्रुप में स्थान बनाया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, टाइम्स हायर एजुकेशन ने कहा कि उच्च भारतीय विश्वविद्यालय शिक्षण और प्रकाशन स्कोर के साथ-साथ अपने शोध, पशुपति पत्र और वैश्विक अनुसंधान सहयोग स्कोर में धीरे-धीरे सुधार कर रहे हैं। गौरतलब है कि यू.के. के आक्सफोर्ड विश्वविद्यालय जिसने एक कोविड-19 वैक्सीन की वैश्विक खोज का मार्ग प्रशस्त किया, ने लगातार छठे वर्ष प्रभावशाली रूप से शीर्ष स्थान बनाए रखा। विश्व स्तर पर 1500 से ज्यादा यूनिवर्सिटीज को इस रैंकिंग में शामिल किया जाता है।

भारतवर्ष में सुदूर अतीत में उच्च शिक्षा की गौरवशाली परम्परा थी। तक्षशिला, नालन्दा, विक्रमशिला, ओदन्तपुरी, काशी, अवन्तिका, पाटलिपुत्र, गांधार, कश्मीर, श्रावस्ती, साकेत जैसे विश्वविद्यालयों का उल्लेख हमें मिलता है। मध्यकाल में मदरसों में उच्च शिक्षा दी जाती थी। जौनपुर, फिरोजाबाद, आगरा, दिल्ली, फतेहपुर सीकरी, बीदर के मदरसे विश्वप्रसिद्ध थे। ब्रिटिश शासन के अन्तर्गत पहले शिक्षा उपेक्षित थी। सन् 1854 के बुड डिस्पैच में विश्वविद्यालयों की स्थापना की बात कही गई। सन् 1857 में कलकत्ता, मद्रास और बम्बई में सर्वप्रथम तीन विश्वविद्यालय खोले गये।

इन तीनों विश्वविद्यालयों का संगठन भी प्रायः एक सा था। प्रधान अधिकारी कुलपति था जो प्रेसीडेन्सी का गवर्नर या गवर्नर जनरल होता था। कुलपति के नीचे उपकुलपति था जो वस्तुतः कार्यकारी के समस्त अधिकारों का उपभोग करता था। विश्वविद्यालय का नियन्त्रण सीनेट के अधीन था। जिसमें फैलो की संख्या निम्नतम तो निश्चित थी किन्तु उच्चतम अनिश्चित। सामान्य प्रशासन की देखभाल के लिए सिण्डिकेट नाम से कार्यकारी समिति थी। इन विश्वविद्यालयों के कार्यों में अनेक दोष विद्यमान थे, फिर भी इन्होंने भारतीय उच्च शिक्षा में पर्याप्त प्रभाव डाला।

सन् 1857 से 1982 तक उच्च शिक्षा— सन् 1882 में पंजाब विश्वविद्यालय भी स्थापित हो गया था। देश में इस समय ग्यारह प्राच्य शिक्षा के कालेज थे, जिनमें लाहौर का कालेज बहुत प्रसिद्ध था। अजमेर एवं अन्य देशी राज्यों में भी कुछ कालेजों की स्थापना हुई। सन् 1882 के भारतीय शिक्षा कमीशन ने सिफारिश की थी कि सिंध, गुजरात, दिल्ली बिहार और मध्य प्रदेश में नये क्रान्ति स्थापित किये जाएँ।

सन् 1882 से 1921 तक उच्च शिक्षा— सन् 1882 में स्थापित पंजाब विश्वविद्यालय का उल्लेख पहले किया जा चुका है। इस विश्वविद्यालय में प्राच्य विभाग (Oriental Faculty) भी था। इसका मुख्य कार्य परीक्षा लेना था, किन्तु कॉलेज भी इसके नियन्त्रण में रह सकते थे। इसके पश्चात् सन् 1887 ई० में प्रयाग विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। यह भी प्रारम्भ में केवल परीक्षा लेने एवं उपाधि देने तक ही अपने कार्य को सीमित किए था। ब्रिटिश भारत में ही शताब्दी के अन्त तक 136 कॉलेज थे।

भारतीय विश्वविद्यालय आयोग की रिपोर्ट के आधार पर सन 1904 में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम (Indian Universities Act) बना। इस कानून ने विश्वविद्यालयों के कार्य क्षेत्र में विस्तार कर दिया। इसके अनुसार विश्वविद्यालय केवल परीक्षा ही न लेकर प्राध्यापकों की नियुक्ति कर सकते थे, वाचनालय, संग्रहालय, पुस्तकालय एवं प्रयोगशालाएँ स्थापित कर सकते थे। अनुसन्धान के विषय में वे नियम भी बना सकते थे।

उपर्युक्त कानून ने विश्वविद्यालयों के संगठन में भी परिवर्तन किया। इसके अनुसार सीनेट के सदस्यों की संख्या पचास से सौ तक हो सकती थी। सदस्यों का कार्यकाल पाँच वर्ष हो गया। कुछ सदस्यों के निर्वाचन की भी व्यवस्था की गई। सिंडीकेट को नियम ने मान्यता प्रदान कर दी और उसमें कॉलेजों के अध्यापकों को भी स्थान मिला। सिंडीकेट को सम्बन्धित कॉलेजों के निरीक्षण का भी अधिकार दे दिया गया। सन् 1904 के नियम ने सरकार को भी यह अधिकार दे दिया कि वह सीनेट के कार्यों को स्वीकृत करे और विश्वविद्यालय के नियमों में भी आवश्यकतानुसार परिवर्तन कर दे। सन 1904 के नियम के कारण पहले तो कॉलेजों की संख्या कुछ घटी, किन्तु बाद में उसमें वृद्धि हो जाती गई।

सन् 1913 में सरकार का शिक्षा पर एक प्रस्ताव आया जिसमें कॉलेजों की शिक्षा की आलोचना की गई और विश्वविद्यालयों द्वारा शिक्षा प्रबन्ध को ही उचित ठहराया गया। इसका परिणाम यह हुआ सैडलर कमीशन की सिफारिशों के परिणामस्वरूप कई विश्वविद्यालयों की स्थापना सन् 1920 में दाका और रंगून में तथा सन् 1921 में अलीगढ़ और लखनऊ में विश्वविद्यालयों की स्थापना हो गई। इस विश्वविद्यालयों में शिक्षा का कार्य उसी नगर में केन्द्रित था सन् 1922 से सन् 1937 तक उच्च शिक्षा इस काल में पुराने विश्वविद्यालयों का पर्याप्त विकास किया गया। कलकत्ता मद्रास बम्बई तथा पंजाब विश्वविद्यालय जो अब तक केवल परीक्षा लेने एवं उपाधि देने तक ही सीमित थे ने शिक्षण। पंजाब विश्वविद्यालय के अन्तर्गत लाहौर में एक कामर्स कॉलेज और कई ऑनर्स स्कूला की स्थापना हुई। इस समय कलकत्ता विश्वविद्यालय ने स्नातकोत्तर शिक्षा पर ही ध्यान दिया आर अनुसन्धान की भी व्यवस्था की। सन 1927 ई. में प्रयाग विश्वविद्यालय का पुनर्गठन किया गया। इससे सम्बद्ध कॉलेजों के लिए आगरा विश्वविद्यालय की स्थापना हुई।

इस काल में पाँच नए विश्वविद्यालयों की स्थापना हुई। सन् 1922 में दिल्ली विश्वविद्यालय स्थापित हुआ। सन् 1923 में मध्यप्रदेश, बरार, तथा सम्बन्धित देशी राज्यों के लिए नागपुर विश्वविद्यालय की स्थापना हुई, जो सम्बन्धात्मक एवं शिक्षणात्मक दोनों है। सन् 1926 में वाल्टेयर में आन्ध्र विश्वविद्यालय स्थापित हुआ। यह भी नागपुर विश्वविद्यालय की भाँति शिक्षणात्मक एवं सम्बन्धात्मक दोनों है। तमिल भाषा के विकास के लिए राजा अन्नामलाई ने बीस लाख रुपये का दान किया और इसके फलस्वरूप विदाम्बरम्, अन्नामलाई नगरद्व में सन् 1929 में अन्नामलाई विश्वविद्यालय स्थापित किया गया। सन् 1927 में आगरा विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी, जो संयुक्त प्रान्त, अजमेर, मध्यभारत एवं राजपूताना के कॉलेजों को स्वीकृति प्रदान करता था।

इस काल में उच्च शिक्षा में बड़ी प्रगति हुई। विश्वविद्यालयों में नए विभाग खुले एवं नए कॉलेजों की स्थापना हुई। छात्रों की संख्या बढ़ कर लगभग सवा लाख हो गई। सन् 1925 में अन्तरविश्वविद्यालय परिषद् (Inter-University Board) की स्थापना हुई जिससे विश्वविद्यालयों में पारस्परिक सहयोग बढ़ा। इस काल में राष्ट्रीय भावना से प्रेरित होकर भारतीय मनीषियों ने कुछ राष्ट्रीय संस्थाओं की स्थापना की, जो उच्च शिक्षा के केन्द्र हैं। सन् 1922 ई. में विश्वभारती की स्थापना हुई। इस काल में जामिया मिलिया के कार्यों में भी प्रगति हुई, यद्यपि इस संस्था की स्थापना सन् 1920 में ही दिल्ली में हो गई थी। मौलाना मोहम्मद अली की जामिया मिलिया संस्था के आदर्श पर कुछ अन्य उच्च शिक्षा संस्थाएँ भी स्थापित हुई। प्रयाग महिला विद्यापीठ, गुजरात विद्यापीठ, काशी विद्यापीठ, तिलक विद्यापीठ पूना, हिन्दी विश्वविद्यालय प्रयाग आदि ऐसी ही संस्थाएँ हैं।

सन् 1937 से 1947 तक उच्च शिक्षा— सन् 1937 में त्रावणकोर में एक विश्वविद्यालय खुला। नये उड़ीसा प्रान्त की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सन् 1943 में उत्कल विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। सन् 1946 में सागर विश्वविद्यालय खुला। सिन्ध के कॉलेज अभी तक पंजाब विश्वविद्यालय से सम्बद्ध थे। सन् 1947 में सिन्ध में एक विश्वविद्यालय स्थापित हो गया, किन्तु स्थापना के शीघ्र बाद ही वह पाकिस्तान में चला गया। उसी वर्ष राजपूताना विश्वविद्यालय भी स्थापित हुआ था। इस काल में उच्च शिक्षा में कुछ प्रगति हुई। सन् 1946-47 के शिक्षा सत्र में देश में 933 कॉलेज थे जिनमें लगभग दो लाख विद्यार्थी शिक्षा प्राप्त कर रहे थे।

डॉ. श्रीमाली समिति के सुझावों के अनुसार ग्राम विद्यापीठों की स्थापना की गई है। शान्तिनिकेतन, तुर्की, बिचपुरी, गाँधीग्राम, मदुराई, कोयम्बटूर, गारगोटी, उदयपुर आदि स्थानों पर ये विद्यापीठ खोले गये थे। देश के विभिन्न भागों में स्थित ग्रामविद्यापीठों की संख्या उस समय ग्यारह थी। इन विद्यापीठों में समाज-शिक्षा, समाज-कार्य, सहकारिता, जन-प्रशासन, ग्रामीण उद्योग-धन्धे, सिविल और रूरल इंजीनियरिंग, कृषि-विज्ञान आदि पाठ्यक्रमों के शिक्षण की व्यवस्था थी। ग्राम-विद्यापीठ में ग्राम सेवा (Rural Services) का पाठ्यक्रम उच्चतर माध्यमिक शिक्षा के पश्चात् तीन वर्ष का था। इस पाठ्यक्रम को बी. ए. के समकक्ष माना गया था। ग्रामीण उच्च शिक्षा के विषय में परामर्श देने के लिए एक राष्ट्रीय ग्रामीण-उच्च-शिक्षा परिषद् का गठन किया गया था।

स्वतंत्र भारत में उच्च शिक्षा— अगस्त 1947 में भारत को स्वतंत्रता प्राप्ति हो गई। स्वतंत्रता प्राप्त होते ही उच्च शिक्षा में सुधार को आवश्यकता प्रतीत हुई। इसलिए शिक्षा मंत्रालय ने दिसंबर, सन् 1948 में डॉ. सर्वपल्लो राधाकृष्णन की अध्यक्षता में विश्वविद्यालयीय शिक्षा की जांच करने के लिए एक आयोग की नियुक्ति की। अध्यक्ष के अतिरिक्त आयोग के अन्य सदस्य थे डॉ. ताराचंद, डॉ. सर जेम्स एफ. डफ. (डरहम विश्वविद्यालय के उपकुलपति), डॉ. जाकिर हुसैन, डॉ. आर्थर ई. मार्गन (अमेरिका), डॉ. ए. लक्ष्मणस्वामी मुदालियर, डॉ. मेघनाद साहा, डॉ. कर्मनारायण बहल, डॉ. जान जे. टिगर्ट (अमेरिका के भूतपूर्व शिक्षा कमिशनर) और श्री निर्मल कुमार सिद्धांत।

राधाकृष्णन की अध्यक्षता में नियुक्त विश्वविद्यालय आयोग ने 25 अगस्त, 1949 को अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। आयोग का क्षेत्र बड़ा विस्तृत था। अंतरराष्ट्रीय परिस्थितियों को देखते हुए तथा भारतीय परिस्थितियों की जांच करते हुए आयोग को उच्च शिक्षा के उद्देश्य, पाठ्यक्रम, संगठन एवं प्रशासन, माध्यम आदि सभी विषयों पर विचार करना था।

आयोग ने भारतीय विश्वविद्यालयों के सभी अंगों का अध्ययन करके अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। प्रतिवेदन का प्रथम भाग अठारह अध्यायों तथा 747 पृष्ठा में है। सरकार ने 1953 में विश्वविद्यालय अनुदान समिति को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग में बदल दिया और 1956 में एक कानून द्वारा इसे स्वायत्त संस्था का दर्जा प्रदान किया। सरकार ने 1954 में ग्रामीण उच्च शिक्षा समिति की स्थापना की। स्नातक पाठ्यक्रम को तीन वर्षीय कर दिया गया।

इस प्रकार देश में उच्च शिक्षा निरन्तर प्रगति पथ पर है। इसके दोषों का निवारण होने पर एवं मूल्यों पर बल देने पर इसकी उन्नति और भी अधिक तीव्रगामी हो सकती है। हमें शिक्षा (विद्या) के मूल उद्देश्य के प्रति सचेष्ट रहना है, और यह मूल उद्देश्य हमारे शैक्षिक मूल्य का प्रतीक है। इसे प्राचीन भारतीय विद्वानों ने अति संक्षिप्त एवं सारगर्भित शब्दों में व्यक्त किया—

“विद्या ददाति विनयम्, विनयात्, याति पात्रताम्”।

पात्रत्वात् धनमाप्नोति, धनात् धर्मम् ततः सुखम्।।”

(विद्या से विनम्रता, विनम्रता से पात्रता (योग्यता) योग्यता से धन प्राप्ति, धन से धर्म पालन (उत्तरदायित्व का निर्वाह) एवं जीवन में आनन्द प्राप्त होता है।)

REFERENCES

1. आर. ए. शर्मा (2011)। *शिक्षा के दार्शनिक एवं सामाजिक मूल आधार*। मेरठ: आर. लाल बुक डिपो।
2. कपिल, एच.के. & सिंह, ममता (2013)। *सांख्यिकी के मूल तत्व*। आगरा: अग्रवाल पब्लिकेशन्स।
3. कौल, लोकेश (2012)। *शैक्षिक अनुसंधान की कार्य प्रणाली*। नोएडा: विकास पब्लिशिंग हाउस प्राइवेट लिमिटेड।
4. गैरेट, एच.ई. (2000)। *शिक्षा और मनोविज्ञान में सांख्यिकी के प्रयोग*। लुधियाना: कल्याणी पब्लिशर्स।
5. पलोड़, सुनिता & लाल, आर.बी. (2008)। *शैक्षिक चिन्तन एवं प्रयोग*। मेरठ: आर.लाल बुक डिपो।
6. पाठक, पी.डी. (2013)। *भारतीय शिक्षा और उसकी समस्याएँ*। आगरा: विनोद पुस्तक मन्दिर।
7. मदान पूनम (2015)। *भारत में शिक्षा व्यवस्था का विकास तथा समस्याएँ*। आगरा: अग्रवाल पब्लिकेशन्स।
8. बैस्ट, जे. डब्ल्यू. (2011)। *रिसर्च इन एजुकेशन*। नई दिल्ली: पी.एच.आई. लर्निंग प्राइवेट लिमिटेड।
9. राय, पी. & राय, सी. पी. (2012)। *अनुसंधान परिचय*। आगरा: लक्ष्मी नारायण अग्रवाल।
10. शर्मा, आर.ए. (2011)। *भारतीय शिक्षा प्रणाली का विकास*। मेरठ: आर.लाल बुक डिपो।
11. Aggarwal, J. C. (1981). *Theory and principles of Education*. New Delhi: Vikas Publishing House PVT LTD.
12. Best, J. W., & Kahn, J. V. (2014). *Research in education*. Delhi: PHI Learning Private Limited.
13. Mukerji, S. N. (1958). *An introduction to Indian Education*. Baroda: Acharya book depot.
14. Nalwa, V. (1992). *The ABC of research for behavioural & social sciences*. New Delhi: Wiley Eastern Limited.
15. Seetharamu, A.S. (1989). *Philosophies of Education*. New Delhi: Ashish Publishing House.
16. Singh, R.K. (2010). *Mechanics of research writing*. Bareilly: Prakash book depot.
17. Taneja, V. R. (1986). *Educational Thought and*

Practice. New Delhi: Sterling Publishers Private Limited.

वेबसाइट—

1. www.google.com
2. www.sodhganga.inflibnet.ac.in